

[Shri Annasaheb P. Shinde]

versions) under sub-section(1) of section 619A of the Companies Act, 1956.—

- (i) Annual Report of the Punjab Agro-Industries Corporation Limited, Chandigarh, for the year 1971-72 along with the Audited Accounts and the comments of the comptroller and Auditor General thereon
 - (ii) Annual Report of the Mysore State Agro-Industries Corporation Limited, Bangalore, for the year 1972-73 along with the Audited Accounts to the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon,
 - (iii) Annual Report of the Himachal Pradesh Agro Industries Corporation Limited Simla, for the year 1972-73 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor-General thereon,
- (2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Report mentioned at (i) above

[Placed in Library See No LT-8368/74]

SHRI JYOTIRMOY BOSU The first report to be laid under this item is that of the Punjab Agro-Industries Corporation Limited, Chandigarh for the year 1971-72, the second report relates to the year 1972-73 and the third report relates to the year 1972-73 and that is in respect of the Himachal Pradesh Agro Industries Corporation Limited Simla What was Mr Shinde doing there? Did he go to sleep, Sir?

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) He has given the reasons already

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I do not accept the reasons.

SHRI ANNASAHAB P. SHINDE:

I have explained the reasons.

SHRI JYOTIRMOY BOSU I do not accept the reasons

ANNUAL ACCOUNTS AND AUDIT REPORT OF PARADEEP PORT TRUST FOR 1972-73

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B SHANKARANAND) On behalf of Shri Pranab Kumar Mukherjee, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Accounts of the Paradip Port Trust for the year 1972-73 and the Audit Report thereon (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 103 of the Major Port Trusts Act 1963 [Placed in Library See No LT-8369/74]

SHRI JYOTIRMOY BOSU Here too, it relates to the year 1972 73

12 21 hrs

STATEMENT RE OWNERSHIP OF LAND BELOW THE SEA WITHIN TERRITORIAL WATERS

MR SPEAKER Now, Mr Gokhale is to make a statement

श्री मधु लिमये : (बांका) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह किस प्रक्रिया, किस नियम के तहत हो रहा है? क्या यह 372 के तहत है? क्या यह डायरेक्शन 115 के तहत है? यदि ऐसा है तो मेरा पहले होना चाहिए। (व्यवधान) आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं एक एक नियम को लेकर बोल रहा हूँ। अभी खत्म करता हूँ।

क्या यह 357 के तहत है—व्यक्तिगत स्पष्टीकरण? अगर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है तो 115 (बी) डायरेक्शन का देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ने जब उन का स्टेटमेंट आया तो कुछ और चीज इस में पैदा की जो कि उन्हें स्पष्टीकरण के लिए मैंने भेज दी।

श्री मधु लिमये : आप देख लीजिए, यह प्रिविलेज का सवाल बनता है या नहीं और इस के ऊपर मुझे सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ने स्पष्टीकरण मांगा वह मैंने दिला दिया, अब प्रिविलेज इस में क्या होता है क्या नहीं, जिस बात में आप को शक था, उन्होंने कहा कि इस में कोई फर्क नहीं है, फिर भी मैंने उन में कहा कि जो भी स्पष्टीकरण देना है दे दीजिए। आप एक तरफ एनराज उठाने हैं दूसरी तरफ कहते हैं कि स्टेटमेंट न दे।

SHRI MADHU LIMAYE How can you abdicate your responsibility?

मेरा प्रिविलेज

का सवाल है। मैं मुन्गा इन को। इस के बाद आप मुझ का सुनिए।

MR SPEAKER I did not find any ground for privilege in it I have allowed the hon Minister, and I shall allow the hon Member also to make his submissions.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): In my earlier statement made on 2nd May, 1974, I referred to the scheme of reclamation formulated by the Government of Maharashtra relating to the foreshore and stated that the right of the State Government to reclaim the foreshore land was based on the local legislation and that it did not contravene article 297 of the Constitution. I thus explained the legal position relating to reclamation of foreshore. I did not state then that

the Maharashtra Scheme was confined to foreshore only.

In a notice given on 8th May, 1974, the Member alleged that I had made a mis-statement that the Maharashtra Scheme was confined to the foreshore. On 8th August, 1974, I denied this allegation. Thereafter in a Notice dated 16th August, 1974, the Member made an attempt to prove how I had made a mis-statement I submit that I never said that the Maharashtra Scheme was confined to foreshore only. It was never my intention to deal with the factual aspect of the case, as I am concerned only with the legal aspect of the matter; nor do I propose to deal with the factual aspects, namely, whether the Scheme covers land beyond the foreshore.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के सामने उन के 2 मई के वकनव्य में से एक जुमला—प्राखरी जुमला—पेश करता हूँ, जिस के आधार पर आप फैसला कर सकते हैं। गोखले साहब ने 2 मई के वकनव्य में कहा था—

"In conclusion, it might be stated that the reclamation of the foreshore by the Maharashtra Government under the scheme of reclamation formulated by them did not contravene article 297 of the Constitution".

क्या इस का मतलब यह नहीं होता है कि रिक्लेमेशन की स्कीम केवल फारशोर तक सीमित है . . .

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री मधु लिमये : नहीं कैसे? अध्यक्ष महोदय, आप फैसला कीजिए—इस का इम्पलाइड सीनिंग बिलकुल साफ है। मेरी यह गुजारिश है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा फैसला मत मांगिये ।

श्री मधु लिखये : फिर किन का फैसला मांगूं ;—क्या गोखले साहब का या इंदिरा गांधी का फैसला मांगूं ? अध्यक्ष महोदय, मैं तो आप ही से फैसला मांगूंगा ।

MR. SPEAKER: I am not concerned with the decision on it. It is a legal question.

श्री मधु लिखये : अध्यक्ष महोदय, इस में यह स्टेटमेंट है—

“Scheme of Reclamation formu-
lated by them”.

By whom? By the Maharashtra Government. He stated:

“...did not contravene article 297 of the Constitution.”.

इसका साफ मतलब है कि इन की राय में बैंक वे रिक्लेमेशन स्कीम केवल फोरशोर तक सीमित है अगर वे मेरी इस कन्टेंटन को मानते हैं तो मेरा कहना है कि इस टैरिटोरियल वाटर्स के नीचे जमीन भी इस रिक्लेमेशन में आई है मैं मैप्स ला कर आप के सामने रखने के लिये तैयार हूँ आप उन को भी बुला लीजिये । मैं नैबीके मैप्स पेश कर साबित करूंगा कि इस रिक्लेमेशन की स्कीम में टैरिटोरियल वाटर्स के नीचे की जमीन भी आई है जो आप की जमीन थी लेकिन आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं । 2 करोड़ 80 लाख रुपये की रिफवत खाती 16 प्लाट्स की जिन्की में ली गई है । अध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं । बल्कि उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फोरशोर तक इन की स्कीम सीमित है ।

अध्यक्ष महोदय, यह फैसला का सवाल है आप गोखले साहब और सरदार स्वर्ण सिंह जी को बुला लीजिये मैं नैबी के मैप्स ले कर आता हूँ मैं इंप्रिन टाइड टैबिलर और बम्बई रिक्लेमेशन स्कीम भी ले आता हूँ—मैं आप के सामने साबित करूंगा कि निश्चित रूप से इनके के कुछ ब्याक्स ऐसे हैं जो टैरिटोरियल वाटर्स में हैं यानी साल भर, 24 घण्टे पानो के नीचे यह जमीन रहती है आप इस के बारे में अपना फैसला दीजिये मैं सारे दस्तावेज आप के सामने रखने का तैयार हूँ—आप उस में सरदार साहब को बुला लें, गोखले साहब को बुला लें और इधर से अपोजीसन वालो को भी बुला लीजिये मैं साबित करने को तैयार हूँ—मेरा बेलेंज है गोखले साहब को ।

MR. SPEAKER: I am not here to sit in judgment over it. I am not concerned with the legal aspect of it. I am not sitting here as a judge of a High Court. I am sitting here as the Speaker to allow the hon. Member to put his case and to allow the hon Minister also to be put his case.

श्री मधु लिखये : इस क्या कानूनी सवाल है यह तो तथ्यो फैसला का सवाल है अगर इस तरह से मंत्री महोदय, गलन बयानी करते जायेंगे तो कैसे चलेगा ।

MR SPEAKER These are legal matters. I shall allow the hon. Member to put his case and not to go into the legal aspects and ask for a legal finding on it. You can just go to Shri Anthony, engage him, get his opinion and go to the court. He is a topmost lawyer. He will be very much helpful as a member of the Lok Sabha.

श्री मधु लिमये : आप हमारी बात सुन लीजिये अपने चेम्बर में इन दोनों मिनिस्ट्रों और अपोजीसन वालों को बुला लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : बीसियों बातों को यहाँ डील करना पड़ रहा है, अब आप चाहते हैं कि एक कोर्ट अन्दर लगा लूं मेरे को तो यही बरदास्त करना मुश्किल है ।

श्री मधु लिमये : आप अक्मर चेम्बर में बुलाते हैं चूंकि यह मामला सरकार के लिये एबरेरेसिग है, इस लिये नहीं बुलाना चाहते हैं ।

MR. SPEAKER: I cannot accept that position.

श्री मधु लिमये : आखिर चेयर का फंक्शन क्या है ? चेयर सदन के अधिकारों की रक्षा करता है ।

The minister has told a blatant lie. a white lie.

ऐसा लगता है कि आप उन को बरी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस काम को मैं नहीं करूंगा

श्री मधु लिमये : आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा यह सदन के विषेवाधिकारो का मामला है । चलिए आप को बरी कर दिया । गोखले साहब , आप बड़े भाग्यवान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बरी करने वाले कौन हैं ?

STATEMENT BY MEMBER RE:
 REPLY TO SUPPLEMENTARY ON
 S. Q. NO. 225 ABOUT PAYMENT
 TO RAILWAY EMPLOYEES FOR
 THE STRIKE PERIOD

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN
 (Colombatore): Mr. Speaker, Sir, On 6th August 1974 while replying to a supplementary arising out of starred question No. 225, Shri Mohd. Shaif

Qureshi gave an answer which is contrary to facts.

My supplementary question was as follows:

"Sir, I would like to know from the Honourable Minister, of these re-instated cases, how many have been demoted...?"

In his reply, the Minister stated that..... "All appeals are being decided on merits. All these people have been taken back on the original posts. There has been no case of demotion so far."

I have, with me, Sir, documents to prove that the Minister was not giving correct information in his reply. To quote only one example, on 16th July 1974, that is three weeks before the Minister gave his reply, the following order was served on one Shri J. P. Srivastava, an employee in the Allahabad Division of the Northern Railway:

"Letter No. 230. Elect|RSO|Conf|
 ZZ|74 (Appeal|127A|1974, dt.
 16.7.74)

From: D.P.O. N. Rly., Ald to Sr.
 J. P. Srivastava c/o T. F. R.
 Ald.

The Divl. Supdt. has considered your appeal quoted above in terms of Rules 1968 and passed the following order which may please be noted.

He was an active participant in the strike. He even gave press statement exhorting people to go on strike. We may take him back but revert him as fireman Gr. C. permanently break in service to be enforced.

You are accordingly directed to report to Loco Foreman, Ald. to take up your duty as fireman Gr. C. immediately. The intervening period between the date of your dismissal from service and date of reinstatement would be treated as break in service for all purposes."